एस. एस. संधवालिया सी. जे. और एस. एस. कांग जे. के समक्ष

हर नारायण,-अपीलार्थी

बनाम

राम लाल और अन्य-उत्तरदाता।

1977 का पत्र पेटेंट अपील सं. 223

16 जुलाई, 1980

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 16-रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ के पास पदोन्नति के विभिन्न माध्यम हैं-रेलवे बोर्ड ने सेवा को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करने वाली एक समान नीति विकसित की है-निर्णय से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों को भर्ती के दौरान अपनी पदोन्नति की लाइन चुनने का अंतिम विकल्प दिया जाता है। जबकि इसके बाद भर्ती होने वालो को पदोन्नति के संयुक्त चैनल का पालन करनाहोता है - ऐसा वर्गीकरण - चाहे वह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो - नीतिगत निर्णय से पहले भर्ती किए गए रेलवे कर्मचारी एक निश्चित माध्यम के लिए पदोन्नति के विकल्प का उपयोग करते हैं - ऐसे कर्मचारी को - क्या अपने विकल्प पर वापस जाने और पदोन्नति की दूसरी पंक्ति चुनने की अनुमति दी जा सकती है - नीतिगत निर्णय को स्पष्ट करने वाले निर्देश - क्या किसी विशेष व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उल्लंघनकारी हो सकता है।

माना गया, कि रेलवे बोर्ड के नीतिगत निर्णय ने एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा कर दिया और इसलिए पदोन्नति के चैनलों के वास्तविक अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न हुई जटिलताओं की गॉर्डियन गाँठ को काटने के लिए वाटर-शेड प्रदान किया। इसलिए, यह प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति नीतिगत निर्णय से पहले सेवा में शामिल हुए थे, उन्हें अपनी पदोन्नति की लाइन चुनने का अंतिम स्वैच्छिक विकल्प दिया जाएगा, जबकि उस तिथि के बाद शामिल होने वाले लोग वास्तव में ऐसे विकल्पों से वंचित थे और पदोन्नति की संयुक्त या सामान्य लाइन का पालन करने के लिए बाध्य थे। यह बात उनके सामने साफ़ थी कि जो लोग नीतिगत निर्णय से पहले सेवा के सदस्य थे, उन्होंने स्वेच्छा से पदोन्नति के एक निश्चित चैनल को स्वीकार करने के लिए अपने स्वैच्छिक विकल्प दिए थे और अन्य प्रतिद्वंद्वी चैनल में कोई भी बेहतर संभावना दिखाई देने पर इससे पीछे नहीं हट सकते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि विशिष्ट संदर्भ में नीतिगत निर्णय की तारीख उन व्यक्तियों को विकल्प देने का औचित्य और अंतर्निहित आधार थी जो पहले सेवा में थे, जबकि उस तारीख से देर से आने वालों को विकल्प देने से इनकार कर दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट होगा कि नीति निर्णय की तारीख से पहले सेवा में शामिल होने वाले व्यक्तियों को एक वर्ग के रूप में माना जाता है और उसके बाद नए प्रवेशकों को दूसरे के रूप में माना जाता है। इस वर्गीकरण से थोड़ा झगड़ा किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि भेदभाव तभी उत्पन्न होता है जब एक ही वर्ग के व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 16 एक उचित वर्गीकरण पर प्रहार नहीं करता है और तय

नीतिगत निर्णय की तारीख से निर्धारित वर्गीकरण किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित नहीं है। यह अच्छी तरह से ध्यान में रखा जा सकता है कि जहां तथ्यों की आवश्यकता है, वहां एक ही सेवा में भी भेद या वर्गीकरण को स्वीकार्य माना गया है। (पैरा 13 और 14)

आयोजित किया गया।कि यदि कोई निर्देश या वैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है, तो उसे समग्र रूप से असंवैधानिक के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए, न कि केवल किसी विशेष व्यक्ति के अधिकारों पर इसके विशिष्ट प्रभाव के संबंध में।(पैरा 8)

23 मई के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड *X* के तहत लेटर्स पेटेंट अपील। *1977,* माननीय न्यायाधीश प्रेम चंद जैन द्वारा *1973* के सिविल रिट संख्या *682 [*बी. ए. एम. एल. डी. एल बनाम।जनरल मानेर *(*पी.*)* मुख्यालय कार्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली और अन्य।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एम. आर. अग्निहोत्री।

एन. के. सोधी, प्रतिवादी संख्या *1* के लिए अधिवक्ता

न्याय

एस. एस. संधवालिया, सी. जे.

(1) ये दो अपील हर नारायण और महाप्रबंधक रेलवे, अपीलकर्ताओं द्वारा संदर्भित,विद्वान एकल न्यायाधीश के उसी निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं जिसके तहत उन्होंने अनुलग्नक 'जी' में शामिल निर्देशों को केवल उस हद तक रद्द कर दिया, जहां तक इनसे राम लाल प्रतिवादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उन्हें परिणामी राहत दी गई। इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले कानून और तथ्य के मुद्दे समान होने के कारण, पार्टियों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि यह निर्णय उन दोनों को नियंत्रित करेगा।

2. राम लाल, प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, 17 जून, 1957 को रुपये 60—130 के ग्रेड पर टिकट कलेक्टर ग्रेड 1 के रूप में रेलवे सेवा में शामिल हुए। प्रतिवादी रुपये 150-240 के ग्रेड में टिकट कलेक्टर ग्रेड II के या रुपये 130—212 के ग्रेड में यात्रा टिकट परीक्षक के, पदोन्नति योग्य पदों के लिए इच्छुक हो सकता था। यह स्वीकार किया गया है कि 12 जुलाई, 1962 से पहले, इन उच्च पदों पर पदोन्नति की पद्धति इस आशय की थी कि संबंधित मंडल कार्मिक अधिकारी टिकट कलेक्टरों को अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कह सकते थे, यदि वे भविष्य में अपनी उन्नति टिकट संग्राहकों या यात्रा टिकट परीक्षकों के उच्च ग्रेड के चैनल में चाहते हों। प्रतिवादी राम लाल के स्वयं के प्रदर्शन पर 1962 के बाद भी उन्होंने स्पष्ट रूप से रुपये 130-212 के ग्रेड में यात्रा टिकट परीक्षकों के चैनल को चुनने के अपने विकल्प का प्रयोग किया और वे उक्त पद पर थे, जब उन्होंने रिट याचिका दायर की। उनका दावा था कि यात्रा टिकट परीक्षक और टिकट संग्राहक के पद समकक्ष थे और भविष्य की पदोन्नति के उद्देश्य से एक संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जा रही थी जिसमें प्रतिवादी राम लाल को अपीलकर्ता हर नारायण से वरिष्ठ दिखाया गया था। यह बताया गया कि हर नारायण अपीलकर्ता को 1 सितंबर, 1962 को टिकट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि प्रतिवादी को बहुत पहले नियुक्त किया गया था।

3. अब, यह सामान्य मामला प्रतीत होता है कि पूरे रेलवे के टिकट संग्राहकों और यात्रा टिकट परीक्षकों दोनों के लिए लागू पदोन्नति के एक एकीकृत चैनल का पेचीदा मुद्दा काफी समय तक अधिकारियों की जांच के अधीन रहा। इसे हल करने के लिए, रेलवे बोर्ड ने गहन जांच के बाद अंततः 12 जुलाई, 1962 को निर्देश, अनुलग्नक 'ई' जारी किया, जिसमें प्रक्रिया, तरीके और उसके बाद पालन किए जाने वाले विकल्पों की संख्या को सटीक रूप से निर्धारित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुलग्नक 'ई' के लागू बारे कुछ संदेह अभी भी बने हुए हैं और तब रेलवे बोर्ड ने तत्संबंधी, आक्षेपित नीति पत्र, अनुलग्नक 'जी', दिनांक 31 जुलाई, 1968 द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया।

4. फिर यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण के बाद भी, - अनुलग्नक 'जी' के तहत, प्रतिवादी राम लाल ने अपनी इच्छा से पदोन्नति के चैनल के लिए अपने विकल्प का विधिवत प्रयोग किया। हालाँकि, रुपये 250-380 के वेतनमान में वरिष्ठ कंडक्टर का एक पद जिसे अनुसूचित जाति के एक सदस्य द्वारा भरना आवश्यक था, बाद में खाली हो गया और प्रतिवादी राम लाल उस पर दावा करना चाहते थे। उनकी शिकायत थी कि अनुलग्नक 'जी' द्वारा पदोन्नति के चैनल के संबंध में एक अन्य विकल्प का प्रयोग करने का उनका कथित अधिकार छीन लिया गया था और परिणामस्वरूप रिक्त पद पर उनका दावा खारिज कर दिया गया था और इसलिए, उक्त नीति पत्र संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन था। एक आवश्यक राहत के रूप में रिट याचिकाकर्ता (प्रतिवादी राम लाल) ने दावा किया कि उसे एक प्रमोशनल कोर्स में भेजा जाना चाहिए, जिसमें उत्तीर्ण होना कंडक्टर के पद पर चयन के लिए एक शर्त थी और उसने उक्त कोर्स में अर्हता प्राप्त करने के लिए हर नारायण अपीलकर्ता के विवरण को चुनौती दी।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि जुलाई, 1962 से पहले सेवा में शामिल होने वाले सदस्यों और उसके बाद नियोजित लोगों के बीच अनुलग्नक 'जी' के माध्यम से जो अंतर करने की मांग की गई थी, वह स्थायी नहीं है क्योंकि वे रिट-याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, रिट याचिका मंजूर की गई और परिणामस्वरूप राम लाई प्रतिवादी को जोनल ट्रेनिंग स्कूल, चंदौसी में भेजने की राहत दी गई, हर नारायण अपीलकर्ता को वहां से बाहर कर दिया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का क्रियाशील और अंतिम भाग निम्नलिखित शब्दों में है: -

“इसलिए, मेरी राय है कि निर्देश, जो याचिकाकर्ता के प्रतिवादी नंबर 3 के पहले वरिष्ठ कंडक्टर के चयन ग्रेड के लिए अधिकार पर विचार किए जाने को प्रभावित करते हैं, सच में भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, मैं इस याचिका को लागत सहित स्वीकार करता हूं, मेमो क्रमांक 522 ई/15 (एसआईसी)दिनांक 31 जुलाई 1968, में निहित निर्देश को रद्द करता हूं, दिनांक 31 जुलाई, 1968 के संलग्नक 'जी' की प्रतिलिपि जहां तक याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है और आदेश संख्या 843 ई/89 पी. आई. ए., दिनांक नवंबर, 1972, संलग्नक 'एच' की प्रतिलिपि जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को पदोन्नति पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, और आधिकारिक प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को क्षेत्रीय

प्रशिक्षण विद्यालय चंदौसी में पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजने का निर्देश देता है, और उसे 250-380 रुपये के ग्रेड में वरिष्ठ कंडक्टर के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार करता है"

6. प्रारंभ में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एम. आर. अग्निहोत्री ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुलग्नक 'जी' को पूरी तरह से रद्द नहीं किया था, बल्कि केवल यह माना था कि यह केवल तब तक गलत था जब तक यह प्रतिवादी राम लाल के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता था। प्रतिवादी राम लाल के वकील ने बताया कि न तो रिट याचिका में कोई मामला बनाया गया था और न ही यह माना गया है कि अनुच्छेद 16 के कथित उल्लंघन के मद्देनजर अनुलग्नक 'जी' पूरी तरह से अमान्य था। इन मान्यताओं पर श्री अग्निहोत्री ने इस आधार पर दृढ़तापूर्वक फैसले को चुनौती दी कि या तो विवादित पत्र अनुलग्नक 'जी' अनुच्छेद 16 का उल्लंघन था और इसलिए अमान्य और शून्य था या यह सभी व्यक्तियों के लिए वैध था। यह बहुत दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया था कि उक्त निर्देश अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जहां तक कि वे याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भेदभाव के नियम का सार यह है कि यह संपूर्ण कार्रवाई या प्रावधान को असंवैधानिक बना देगा।

7. यह प्रतिवादी श्री एन.के. सोढ़ी के विद्वान वकील का श्रेय है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह एकल न्यायाधीश के फैसले को कायम रखने में केवल इसलिए असमर्थ थे क्योकि निर्देश, अनुलग्नक 'जी' जब तक प्रतिवादी राम लाल के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, केवल भेदभावपूर्ण हैं और इससे अधिक नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि या तो अनुलग्नक 'जी' या किसी भी मामले में उसका विशिष्ट भाग समग्र रूप से न केवल प्रतिवादी राम लाल के संबंध में और सभी व्यक्तियों के लिए अमान्य होगा। इतना स्वीकार करने के बाद श्री सोढ़ी को व्यर्थ ही एक कोने में धकेल दिया गया कि वर्तमान अपीलों में हमें अब बिना किसी सीमा के अनुबंध 'जी' को रद्द कर देना चाहिए और इसके कथित भेदभावपूर्ण प्रभाव को केवल विद्वान एकल न्यायाधीश की तरह ही सीमित नहीं रखना चाहिए।

8. हमें डर है कि वास्तव में उपरोक्त स्वीकृत स्थिति पर अपील के तहत निर्णय अस्थिर हो जाएगा। एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है (जैसा कि यह अनारक्षित रूप से किया गया है) तो एक निर्देश या वैधानिक प्रावधान यदि संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है तो इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए और न केवल किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों पर इसके विशिष्ट प्रभाव के संबंध में, यह स्पष्ट होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का क्रियाशील हिस्सा बरकरार नहीं रखा जा सकता।

9. जहां तक श्री सोढ़ी की प्रार्थना का संबंध है, अब हमें अनुलग्नक 'जी' पूरी तरह से अमान्य मानना चाहिए, हम उसके रास्ते में एक दुर्गम बाधा पाते हैं। यह माना गया है कि राम लाल प्रतिवादी ने दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलों, जो अब हमारे सामने है में न तो कोई क्रॉस अपील दायर की थी और ना ही कोई क्रॉस-आपत्ति दी गई थी। इसलिए, इन अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई अपीलों में उनके लिए दिए गए आदेश जिसे चुनौती दी गई है, से भी अधिक प्रतिकूल कोई भी आदेश शायद ही पारित किया जा सकता है। आगे विद्वान एकल न्यायाधीश का फैसला यह दर्शाएगा कि उसने (अपीलकर्ता की ओर से जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि उसके समक्ष तथ्यो पर, वास्तव में वह नहीं कर सका) निर्देशों को समग्र रूप से अमान्य नहीं माना। इसलिए, इन अपीलों में हमें न ही कोई औचित्य, न ही जिज्ञासु को राहत देने की क्षमता मिली जो इस स्तर पर सोढ़ी जी द्वारा प्रतिवादी की ओर से मांगा गया है

10.यद्यपि इस मामले को उपरोक्त संक्षिप्त आधार पर निपटाया जा सकता है तथापि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की रियायत पर या अपीलकर्ताओं के लिए अधिक प्रतिकूल आदेश जिससे वे व्यथित हैं पारित करने में प्रथम दृष्टया असमर्थता पर खुद को पूरी तरह से निर्भर नहीं रखना चाहेंगे। हमने संविधान के अनुच्छेद 16 के उल्लंघन के कारण, अनुलग्नक 'जी' के पूर्णतः अमान्य होने के आधार पर प्रतिवादी के विद्वान वकील को तर्क करने के लिए आमंत्रित किया था। यह दिखाने के लिए उनके द्वारा कोई सार्थक तर्क नहीं उठाया जा सका कि सहज स्पष्टीकरण या स्वयं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी प्रारंभिक नीति पत्र का सर्वोत्तम संशोधन अनुलग्नक 'जी' द्वारा कानूनन या अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार की समानता के अन्य पहलू से कैसे समानता के नियम के प्रतिकूल होगा। विद्वान वकील द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क यह था कि उन व्यक्तियों के बीच अंतर करने की मांग की गई जो 12 जुलाई, 1962 से पहले या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे, यह कोई तर्कसंगत आधार नहीं था।

11.इसमें हमें खेद है कि हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि अनुलग्नक 'ई' और 'जी' के अनुसार किया गया वर्गीकरण असमर्थनीय है। पहले दिए गए तथ्यों का संक्षिप्त विवरण संकेत देगा (और

यह मामला अन्यथा विवाद में नहीं है) कि जो रेलवे सेवा के समान ग्रेड में रहते हुए विभिन्न पदनाम धारण करने वाले और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए पदोन्नति के चैनलों के संबंध में उलझी हुई उलझनें उत्पन्न हुई, इस प्रकार उठाया गया जटिल मुद्दा सभी स्तरों पर विचाराधीन रहा,और ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वयं कर्मचारियों द्वारा गंभीर अशांति और अभ्यावेदन का विषय रहा है अंततः यह मामला रेलवे बोर्ड के स्तर पर सर्वोच्च प्राधिकारी के पास भेजना पड़ा और एकरूपता लाने के लिए, उन्होंने अंततः 12 जुलाई 1962 को नीतिगत निर्णय को निम्नानुसार निर्धारित किया गया है - अनुलग्नक 'ई' के अनुसार: -

"उत्तर रेलवे,   मुख्यालय कार्यालय, बड़ौदा हाउस,

क्रमांक 561/ई/92(डुप)   नई दिल्ली।

उन्नयन (ईआईसी.)।

दिनांक 12 जुलाई, 1962

संभागीय अधीक्षक,

उत्तर रेलवे,

दिल्ली, इलाहाबाद, मोरादाबाद, लखनऊ, फ़िरोज़पुर,

बेकानेर और जोधपुर

विषय: टीसी के पदों का उन्नयन रु. पी. एस. में रु.200-300.

संदर्भ: इस कार्यालय के पत्र संख्या 561 ई/82 (ईआईसी) पर आपके उत्तर,दिनांक 21 नवंबर, 1961.

(1) संपूर्ण रेलवे में टीसीआर/टीटीई पर लागू पदोन्नति का एक एकीकृत चैनल होने का प्रश्न पर इस कार्यालय में काफ़ी समय से विचाराधीन है। अब रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय लिया है निम्नलिखित प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जानी चाहिए।

(2)रुपये 80-160 (पीएस) और रुपये 100—185 (पीएस) तक पदोन्नति, टीसीआर और टीटीई की संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर की जानी चाहिए। जो लोग पहले ही टीटीई कैडर के लिए टीसीआर का विकल्प प्रयोग कर लिया है, उन्हें एक बार फिर से चयन करने का अवसर दिया जा सकता है जब उन्हें उच्च ग्रेड में पदोन्नति दी जानी हो। नए प्रवेशकों को किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पदोन्नति के संयुक्त चैनल का पालन करना होगाजो लोग पदोन्नति के लिए संयुक्त चैनल के लिए नए विकल्प का उपयोग करते हैं, उन्हें पदोन्नति के समय 200 से 300 रुपये (पीएस) तक के विकल्प का एक और अवसर नहीं दिया जाएगा, जबकि जो लोग 100-185 रुपये (पीएस) तक का विकल्प दिए बिना पदोन्नति के संयुक्त चैनल का पालन करते हैं, उन्हें पदोन्नति के चरण में 200-300 (पीएस) तक का विकल्प दिया जाएगा।

3.यह देखा जाएगा कि पदोन्नति के एकीकृत चैनल की शुरुआत के परिणामस्वरूप उच्च श्रेणी केटी. सी. आर. और टी. टी. ई. के लिए संबंधित संवर्गों के आधार पर ग्रेड 200-300 (पी. एस.) और उससे ऊपर पदों का प्रतिशत निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा। इन दोनों संवर्गों की संयुक्त संख्या के आधार पर अब उच्च श्रेणी के पदों पर काम किया जाएगा। हालांकि, दोनों कैडरों के बीच ऐसे पदों का वास्तविक वितरण प्रभार और प्रशासनिक सुविधा पर निर्भर करेगा।

(4)कृपया इन आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुलग्नक 'ई' के माध्यम से उपरोक्त नीतिगत निर्णय को रिट याचिका में या विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और उस मामले में हमारे समक्ष दूर-दूर तक कोई चुनौती नहीं दी गई थी। श्री सोढ़ी ने उत्तरदाताओं के वकील के रूप में स्पष्ट रूप से पूछे जाने पर भी स्वीकार किया कि उनका अनुलग्नक 'ई' के अनुसार निर्धारित नीति से कोई झगड़ा नहीं है,

12. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके वास्तविक अनुप्रयोग में, नीति निर्णय अनुलग्नक 'ई' ने स्वयं कुछ समस्याएं उत्पन्न कीं और टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा इसके सटीक अनुप्रयोग के संबंध में अभ्यावेदन दिए गए।इसे अंततः रेलवे बोर्ड के नीति पत्र द्वारा आक्षेपित अनुलग्नक 'जी' के माध्यम से हल किया गया, जिसमें व्यापक रूप से नोटिस की भी मांग की गई है:-

"उत्तरी रेलवे

मुख्यालय कार्यालयःबड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।

संख्या 522-ई। 15 (ई. आई. सी.)।

1 दिनांक 31 जुलाई, 1968।

विषयःटिकट जाँच कर्मचारियों को बढ़ावा देने का माध्यम।

टिकट जाँच करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व।

संदर्भःआपका पत्र सं. 758-ई/15011 पी2, दिनांक 17 जुलाई, 1968।

इस पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार कार्यालय पत्र क्रमांक. 61 ई/92/डीयूपी/(ईआईसी) दिनांक 12 जुलाई, 1962 नए अतिरिक्त लोगों के लिए कोई विकल्प दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें पदोन्नति के संयुक्त चैनल का पालन करना होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई 1962 से पहले नियुक्त टिकट कलेक्टरों को पदोन्नति दी जा सकती है विकल्प के अनुसार यह प्रावधान करना होगा कि ग्रेड 250 - 360(एएस) की पदोन्नति के समय उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि श्री सोढ़ी को उपरोक्त उद्धृत अनुबंध के पैराग्राफ संख्या 1 से कोई आपत्ति नहीं है। एकमात्र शिकायत उसके दूसरे पैराग्राफ के खिलाफ की जानी है।

13. उपरोक्त से और अनुबंध 'ई' की सामग्री से भी यह स्पष्ट होगा कि नीतिगत निर्णय ने एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा कर दिया और इसलिए, जटिलताओं की गॉर्डियन गाँठ को काटने के लिए जल-शेड प्रदान किया गया जो पदोन्नति के चैनलों के वास्तविक अनुप्रयोग के संबंध में उत्पन्न हुआ था। इसलिए, यह प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति 12 जुलाई, 1962 से पहले सेवा में शामिल हुए थे, उन्हें अपनी पदोन्नति की लाइन चुनने के लिए अंतिम स्वैच्छिक विकल्प दिया जाएगा जबकि जो लोग तिथि के बाद शामिल हुए वे वास्तव में ऐसे विकल्पों से वंचित थे और पदोन्नति की संयुक्त या सामान्य लाइन का पालन करने के लिए बाध्य थे।

जो व्यक्ति 12 जुलाई, 1962 से पहले सेवा के सदस्य थे, उन्होंने अपनी आँखें खुली रखते हुए स्वेच्छा से एक निश्चित चैनल को प्रतिग्रहण करना करने के लिए अपने स्वैच्छिक विकल्प दिया। अब उनके मुँह में मुकरने की बात नहीं रह जाएगी कि वे दूसरे प्रतिद्वंद्वी चैनल में किसी भी बेहतर संभावना के उपलब्ध होने के क्षण से पीछे हटें। अतः यह स्पष्ट होगा कि 12 जुलाई, 1962 को नीतिगत निर्णय की तारीख से पहले सेवा में संलग्नक होने वाले व्यक्तियों को अनुबंध 'जी' एक वर्ग के रूप में और उसके बाद

नए प्रवेशकों को दूसरे के रूप में मानता है।हमारे विचार में इस वर्गीकरण से थोड़ा झगड़ा किया जा सकता है।इसलिए, प्रतिवादी राम लाई एक ही वर्ग से थे, जबकि अपीलकर्ता हर नारायण, 1 सितंबर, 1962 को सेवा में शामिल होने के बाद, नए प्रवेशकों के वर्ग से संबंधित थे। ययह तो अच्छी तरह तय हो चुका है भेदभाव यह तभी उत्पन्न होता है जब एक ही वर्ग के व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 एक उचित वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है और इस संबंध में हम यह मानने में असमर्थ हैं कि वैध निर्णय माने जाने की तारीख से निर्धारित वर्गीकरण किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित है। जहाँ तक प्रत्यर्थी-राम लाई का संबंध है, यह वस्तुतः स्वीकृत स्थिति है और उनके वर्ग के व्यक्तियों, अर्थात् 12 जुलाई, 1962 से पहले सेवा में प्रवेश करने वालों का

संबंध है, उनके साथ निर्देशों द्वारा समान व्यवहार किया जा रहा है।इसलिए, जहां तक इस वर्ग का संबंध है,अनुलग्नक 'जी' और इसके पूर्ववर्ती अनुलग्नक 'ई' समान रूप से कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 16 का प्रयोग या भेदभाव का कोई आरोप,हमें अनावश्यक प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त संदर्भ में इसे भी ध्यान में रखा जा सकता है कि जहां तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं, तो उसी सेवा में भी एक भेद या वर्गीकरण को स्वीकार्य माना गया है। यहाँ जिस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह यह है कि वर्तमान मामले में सेवा में अलग-अलग पदनामों की कई शाखाएँ शामिल हैं और हालांकि ग्रेड समान हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्य व्यापक रूप से अलग हैं। फिर भी उन मामलों में भी जहां कर्तव्य समान हैं और पदनाम समान हैं, कार्रवाई में भेदभाव किए बिना एक रेखा खींचना संभव है। इस संदर्भ में मैसूर राज्य बनाम नरसिंगा राव[1]के रूप में रिपोर्ट किए गए प्रसिद्ध ट्रेसर मामले का संदर्भ दिया जा सकता है। उसी सेवा के भीतर वर्गीकरण को शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर करने की मांग की गई थी, अर्थात्, जो मैट्रिक वाले थे और अन्य जो गैर-मैट्रिक वाले थे, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:—

"* * * अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के प्रावधान चयनात्मक परीक्षणों को निर्धारित करने से बाहर नहीं करते हैं, और न ही वे सरकार को विचाराधीन पद के लिए योग्यता निर्धारित करने से रोकते हैं।इस तरह की योग्यताएं न केवल तकनीकी होनी चाहिए, बल्कि वे सार्वजनिक सेवा के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता से संबंधित सामान्य योग्यता भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है ट्रेसर के पद पर नियुक्ति में सरकार को केवल उम्मीदवारों की विशेष कला में तकनीकी दक्षता को ध्यान में रखना चाहिए था। यह सरकार के लिए खुला है कि वह उम्मीदवारों की सामान्य शैक्षिक उपलब्धियों पर भी विचार करे और उन उम्मीदवारों को वरीयता दे जिनके पास तकनीकी प्रवीणता के अलावा बेहतर शैक्षिक योग्यता है।"

पुनः जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा [2] में, यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि विशेष रूप से पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित शब्दों में उसी सेवा के भीतर एक वर्गीकरण किया जा सकता है:-

इसलिए हमारी राय है कि यद्यपि व्यक्तियों सीधे और पदोन्नति द्वारा सहायक इंजीनियरों के एक सामान्य वर्ग में एकीकृत कर के नियुक्त किया गया था। सहायक इंजीनियरों के वर्ग को, कार्यकारी इंजीनियरों के संवर्ग में पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए, शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यह प्रावधान करने वाला नियम कि डिप्लोमा धारक को छोड़कर स्नातक इस तरह की पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

---

1 ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 249.
2 ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1.

15. इसके बाद इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि यहां स्वीकृत स्थिति यह है कि कोई भी अधिनियम या वैधानिक नियम सेवा में पदोन्नति के चैनलों के प्रश्न को नियंत्रित नहीं करता है। यह मामला केवल रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति में से एक था। वास्तव में, यह केवल उक्त नीति पत्रों से ही था जो प्रतिवादी-राम लाल, विकल्पों के प्रयोग के संबंध में कुछ हद तक अधिकार का दावा करना चाहते हैं। इसमें कोई वैधानिक अधिकार शामिल नहीं है।यहां तक कि श्री सोधी ने भी स्वीकार किया कि रेलवे बोर्ड अपने अधिकार के तहत पहले जारी किए गए नीति पत्र को वापस लेने या इसे बदलने, संशोधन करने या यहां तक कि इस योग्यता के अधीन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा कि ऐसी कार्रवाई भेदभावपूर्ण प्रकृति की नहीं थी। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो रेलवे बोर्ड वास्तव में एक व्यापक रूप से विविध सेवा और पदोन्नति के चैनलों की प्रशासनिक अनिवार्यताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश होगा जो जिसे अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मामला इतना जटिल हो गया था कि कठिनाइयों का पता स्टाफ द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों से स्पष्ट होता है,इस तथ्य को समाप्त करती हैं कि ये लंबे समय तक विचाराधीन रहे और उसके बाद अनुबंध ई के माध्यम से नीतिगत निर्णय विकसित किया गया, इसके बाद और स्पष्टीकरण दिया गया, अनुबंध जी. के माध्यम से ऐसी स्थिति में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब तक समानता के नियमों का घोर उल्लंघन न हो, संवैधानिकता की धारणा को महत्व दिया जाना चाहिए और उन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिनमें दो उचित विचार संभव हैं।

16. यहां तक कि कुछ पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह उजागर किया जा सकता है कि 12 जुलाई, 1962 को रेलवे बोर्ड का मूल नीति पत्र, अनुलग्नक ई, प्रतिवादी-राम लाल की ओर से किसी भी स्तर पर चुनौती या हमला नहीं किया गया था। वास्तव में, श्री सोढ़ी का स्वयं का दृष्टिकोण यह था कि यह अनुबंध किसी भी तरह से असंवैधानिकता के दोष से ग्रस्त नहीं था। एक बार ऐसा होने पर, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि केवल स्पष्टीकरण या कम से कम पिछले नीति पत्र में संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन कैसे होगा, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील किसी भी स्पष्ट संघर्ष को दिखाने में असमर्थ थे। अनुलग्नक ई' और अनुलग्नक 'जी', जो पूर्व के परिशिष्ट का पैराग्राफ मात्र था। यहां भी पहले परिशिष्ट 'जी' को हानिरहित और एकमात्र झगड़ा की मांग दूसरे अनुच्छेद की सामग्री के विरुद्ध की जानी चाहिए जो इस प्रकार है:

उपरोक्त के मद्देनजर, 12 जुलाई 1962 से पहले नियुक्त किए गए टिकट कलेक्टरों को तदनुसार पदोन्नति दी जा सकती है। विकल्प इस प्रावधान के अधीन हैं कि उन्हें ग्रेड 250-380 (एएस) में पदोन्नति के समय एक और मौका नहीं दिया जाएगा।

17.अब, संलग्नक 'ई' और 'जी' में शामिल महत्वपूर्ण बात, जिसे अनिवार्य रूप से एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह तथ्य है कि उन्होंने केवल उन कर्मचारियों को एक विकल्प दिया जो पदोन्नति के चैनल के लिए अपनी पसंद चाहते थे जो उनके हित के लिए सबसे उपयुक्त था।यह स्पष्ट रूप से कई चीजों पर निर्भर करेगा।, एक विशेष पंक्ति में विभिन्न कर्मचारियों से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या, उनकी अपनी उम्र, योग्यता और संभावनाओं के साथ-साथ एक विशेष पंक्ति के लिए पूर्वाग्रह और वरीयता के साथ-साथ कई अन्य बाधाओं के बारे में, जिनके बारे में अकेले विशेष लोक सेवक को पता हो सकता है।अब प्राधिकरण द्वारा दिए गए विकल्प के अधिकार का स्वैच्छिक प्रयोग हमें आसानी से ऐसा नहीं लग सकता है जो समानता के शासन का उल्लंघन करेगा। वास्तव में यह कर्मचारियों में एक बड़ा विवेक निहित करता है कि वे जो कुछ भी उनके हित के लिए सबसे उपयुक्त हो उसे चुनें।हमारे सामने यह विवादित नहीं था कि एक विविध सेवा में, एक नीतिगत पत्र के निर्देश के रूप में व्यक्तियों को उनके अपने विकल्प पर पदोन्नति के एक विशेष चैनल तक सीमित रखना न तो भेदभावपूर्ण होगा और न ही किसी भी तरह से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।वास्तव में ऐसे प्रावधान या विकल्पों की तलाश सेवा कानून में आम है।ऐसा होने पर, जहां केवल एक विकल्प दिया जाता है (एक कर्मचारी को पदोन्नति की एक विशेष पंक्ति चुनने के लिए और बाद वाले ने अपनी इच्छा से उक्त विकल्प का प्रयोग किया था, तो उसे उसी से पीछे हटने से रोका जा सकता है।दावा करें, नया विकल्प केवल इसलिए है क्योंकि बाद के चरण में यह उसके हित को बेहतर तरीके से पूरा करता प्रतीत हो सकता है।

18.उपरोक्त कारणों से, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि संलग्नक 'जी' का हानिरहित अनुच्छेद संख्या 2 किसी भी तरह से आम तौर पर या प्रतिवादी-राम लाल के अधिकारों के किसी विशेष संदर्भ के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है।

19.अंत में तथ्यों का विशेष समूह समान रूप से इंगित करेगा कि प्रतिवादी-राम लाल के साथ किसी भी तरह से अनुचित व्यवहार नहीं किया गया है।अपने स्वयं के प्रदर्शन पर, वे 12 जुलाई, 1962 से बहुत पहले सेवा में शामिल हो गए थे।

यहां तक कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के सीमित वर्ग में भी, छह व्यक्ति; अमर नाथ, बाबू राम, स्वर्ण चंद, लाभ सिंह, हरनेक सिंह और ज्ञान चंद उनसे वरिष्ठ थे जैसा कि लिखित बयान के अनुबंध आर/6 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन सभी व्यक्तियों ने पदोन्नति की एक विशेष लाइन के लिए अपने विकल्प का विधिवत प्रयोग भी किया था। प्रतिवादी-राम लाल को स्वयं परिशिष्ट आर/2 के माध्यम से 26 फरवरी 1969 को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा गया था, स्पष्टीकरण के काफी समय बाद, - परिशिष्ट 'जी, दिनांक 31 जुलाई 1968 के माध्यम से; जारी किया गया था. उन्होंने वास्तव में अपने विकल्प का प्रयोग किया, जैसे अनुलग्नक आर /3 और स्पष्ट रूप से कहा कि वह विशेष टिकट परीक्षक के रुपये 130-212 के ग्रेड का विकल्प चुनेंगे। इस प्रकार उन्होंने खुद को खुली आँखों से और अपनी इच्छा से परिशिष्ट 'जी' के तहत पदोन्नति की एक पंक्ति तक सीमित कर दिया। जाहिर है, इसलिए वह अब इसके बारे में गंभीर शिकायत नहीं कर सकता। अपीलकर्ता-रेलवे श्री आर.पी. चोपड़ा, सहायक कार्मिक ओमसर के अतिरिक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ 6, 7 और 8 में अपने रुख पर सही है कि प्रतिवादी-राम लाल, 3 मार्च 1969 को अपने विकल्प का प्रयोग करते समय ऐसा करना चाहिए। वह जानता है कि खुद को एक श्रेणी तक सीमित रखने से, वह भविष्य में वरिष्ठ कंडक्टर या हेड टिकट कलेक्टर की अन्य दो श्रेणियों में चयन ग्रेड के पद का दावा नहीं कर सकेगा। रिटर्न से यह भी स्पष्ट है कि यहां तक कि प्रतिवादी-राम लाल से वरिष्ठ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी, जिन्होंने अपने विकल्प का प्रयोग किया था, इसी तरह पदोन्नति के अपने द्वारा चुने गए चैनल तक ही सीमित हैं और उन्हें चयन ग्रेड या चयन ग्रेड का दावा करने की अनुमति नहीं दी गई है। अन्य श्रेणियों में उच्च पद। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी-राम लाल ने उन्हीं नीति पत्रों के तहत एक विकल्प का विधिवत प्रयोग किया है और उसका लाभ सुरक्षित कर लिया है, अब वह उत्सुकतापूर्वक दूसरे विकल्प का दावा करेगा जब यह उसके हित को बेहतर ढंग से पूरा करने वाला प्रतीत होगा। इसलिए, हमारा विचार है कि यदि उसे अपने वर्ग के अन्य लोगों के साथ, भले ही वह उससे वरिष्ठ हो, रेलवे बोर्ड द्वारा अपनाई गई एक समान नीति द्वारा ऐसा करने से रोका गया है

20 यह निष्कर्ष निकालते हुए कि संलग्नक 'जी' किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का आम तौर पर या किसी भी सीमित संदर्भ में उल्लंघन नहीं करता है, हम इन दोनों अपीलों को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करने की अनुमति देंगे, और परिणामस्वरूप प्रतिवादी-राम लाल द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर देंगे। हालांकि, लागत के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ कर और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रमाणित द्वारा:
सोनिया (अनुवादक/सहायक)
जिला एवं सत्र न्यायालय,पानीपत